

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 570 राँची, मंगलवार,

8 पौष, 1937 (श॰)

29 अक्टूबर, 2015 (ई॰)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2015

संख्या-06@उ॰नि॰@फूड प्रोसेसिंग नीति-01@2015-3297--राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तथा झारखण्ड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 की योजना संकल्प ज्ञापांक 2744] दिनांक 3 सितम्बर, 2015 के द्वारा अधिसूचित की गयी है।

उक्त नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (State Level Empowered Committee) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

मुख्य सचिव| झारखण्ड| राँची
 विकास आयुक्त| झारखण्ड| राँची
 प्रधान सचिव/सचिव| उद्योग विभाग| झारखण्ड| राँची
 प्रधान सचिव/सचिव| स्वास्थ्य| चिकित्सा| शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग| झारखण्ड| राँची
 प्रधान सचिव/सचिव| कृषि| पशुपालन एवं सहकारिता विभाग| झारखण्ड| राँची
 प्रधान सचिव/सचिव| वन एवं पर्यावरण विभाग| झारखण्ड| राँची
 प्रधान सचिव/सचिव| वन एवं पर्यावरण विभाग| झारखण्ड| राँची
 प्रधान सचिव/सचिव| योजना-सह-वित्त विभाग| झारखण्ड| राँची
 सदस्य
 अध्यक्ष| झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद| राँची
 सदस्य

9. निदेशक] राष्ट्रीय बागवानी मिशन] राँची

- सदस्य - सदस्य

10. सिडबी के प्रतिनिधि झारखण्ड राँची

- सदस्य

- 11. नावार्ड के प्रतिनिधि झारखण्ड | राँची
- 12. संयोजक] राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (बैंक ऑफ इण्डिया) झारखण्ड] राँची -सदस्य
- 13.मे0 रामकृष्ण मिशन] राँची

- सदस्य

- 14. श्री नितीन सर्राफ] फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ; थ्श्रब्ब्प्द्वए राँची सदस्य
- 15. निदेशक उद्योग] झारखण्ड] राँची

- सदस्य सचिव

- 2- क) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने की शक्ति का निर्धारण करने पर निर्णय लेगी ।
 - ख) यह सिमति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु उप सिमति/पदाधिकारों को प्राधिकृत करनें वितीय शक्तियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करेगी ।
 - ग) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा समय-समय पर झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति] 2015 को राज्य में लागू किए जाने संबंधी निगरानी] समीक्षा एवं मूल्यांकन कर सकेगी ।
- 3. इस समिति के द्वारा आवेदकों को विमुक्त अनुदान के गलत उपयोग के मामले में अनुदान की वापसी एवं वसूली का अधिकार निम्नांकित स्थितियों में होगा:-
 - क) यदि परियोजना की निर्धारित अविध अथवा विस्तारित अविध में भी पूर्ण नहीं की जाती है य
 - ख) यदि विमुक्त किए गए अनुदान का उपयोग परियोजना में स्वीकृत मदों/कार्यक्रमों से भिन्न मदों में किया गया हो य
 - ग) यदि संस्थान/संगठन अकार्यशील हो जाए अथवा अनुदान की अंतिम किस्त विमुक्ति के तीन साल के पूर्व संस्था अथवा कार्यक्रम बन्द हो जाए ।
- 4. समिति किसी विशेषज्ञ] संगठन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगी ।
- 5. अनुदान आवेदन के अनुमोदन के छः माह के अन्दर प्रथम किस्त विमुक्ति का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) द्वारा परियोजना अस्वीकृत किया जा सकता है ।
- 6. संबंधित सदस्य अगर अति अपिरहार्य स्थिति में स्वतः भाग नहीं ले सकेंगे तो विशेष रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी को बैठक में भागीदारी हेतु अधिकृत करेंगे ।
- मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य (उद्योग) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
 झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप सिंह, सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (असाधारण) 570—50 ।